

(v) ALLEGED CLOSING DOWN OF FLOOR MILLS IN BIHAR DUE TO REDUCED SUPPLY OF WHEAT QUOTA.

श्री रीतलाल प्रसाद बर्मा (काँडरमा): देश के सभी राज्यों में बड़ी चक्कियां तथा रोलर फ्लोर मिल्स के द्वारा जन वितरण हेतु गेहूँ पीसने के लिए केन्द्र सरकार मासिक गेहूँ आबंटित करती रही है। अप्रैल 1982 में भारत सरकार ने बिहार की 22 बड़ी चक्कियों को 2610 मी. टन तथा 20 रोलर फ्लोर मिलों को 16390 मी. टन गेहूँ आबंटित किया। मई 1982 से केन्द्र सरकार ने बड़ी चक्कियों के कोटे काट कर केवल बड़ी मिलों के लिए गेहूँ आबंटित किया। इससे 28 बड़ी चक्कियां बंद हो गई हैं। ये सभी बड़ी चक्कियां लघु-उद्योग के अन्तर्गत निर्बाधित हैं और इन चक्कियों में कार्यरत सैकड़ों लोगों को भुख-मरी का सामना करना पड़ रहा है। बिहार की जनता फ्लोर मिलों का आटा व्यवहार में कम से कम पसन्द करती है क्योंकि उससे अच्छा बड़ी चक्कियों का आटा स्वास्थ्यवर्धक समझती है। छोटा नागपुर का क्षेत्र इस वर्ष अकाल से पीड़ित है। इन चक्कियों से सैकड़ों मजदूरों को रोजी रोटी मिलती थी। वह बंद हो गई है। बिजली की मिनिमम गारंटी एवं बैंक ऋण जमा तथा अनावश्यक सूदखोरी इन छोटे उद्योगों पर वज्राघात के समान है।

अस्तु, श्रीमन् कृषि एवं आपूर्ति मंत्री से आग्रह है कि अन्य राज्यों की तरह तुरन्त बिहार की बड़ी चक्कियों को 3226 मी. टन मासिक गेहूँ का कोटा चालू किया जाए और सातेला व्यवहार बिहार के इन लघु उद्यमियों के साथ नहीं किया जाए।

(vi) ALLEGED REDUCTION IN QUOTA OF RICE AND WHEAT TO BIHAR.

श्री रामावतार शास्त्री (पटना): वर्षा नहीं होने के कारण सम्पूर्ण बिहार तपती धूप और भीषण गर्मी में जल रहा है। आदरा नक्षत्र की वर्षा में किसान धान का बीज खेतों में डालते थे। परन्तु उसके फल हो जाने से किसानों में सर्वत्र कहराम है। जिन इलाकों में नहरें हैं, उन में भी पानी नहीं रहने से स्थिति और भी खराब हो गई है।

उधर नहर विभाग के अधिकारी भी कुछ नहीं कर रहे हैं। नलकूपों की स्थिति भी अच्छी नहीं है। जो कुछ नलकूप ठीक हैं भी उन से काम नहीं चल पा रहा है।

ऐसी स्थिति में थोक और खुदरा दोनों मूल्यों में वृद्धि हो रही है। गल्ला चोर और मुनाफाखोर जनता को लूटने की ताक में लगे हुए हैं। बिहार में खाद्यान्न की स्थिति गम्भीर बनती जा रही है।

बिहार में राशन की दुकानों में गल्ला सप्लाई करने के लिए भारत सरकार प्रत्येक माह पचास हजार टन चावल और चौबीस हजार टन गेहूँ देती थी जो वहां की आवश्यकता को देखते हुए कम था। परन्तु आश्चर्य और दुःख की बात है कि भारत सरकार ने उस में भी कटौती कर दी है। चावल का कोटा पचास हजार टन से बीस हजार टन और गेहूँ का कोटा चौबीस हजार टन से बीस हजार टन प्रतिमाह कर दिया है। इसका साफ मतलब है कि सरकार आम उपभोक्ताओं को संकट की इस घड़ी में मुनाफाखोरों और गल्लाचोरों के रहमो-करम पर छोड़ देना चाहती है। इसका परिणाम स्पष्ट है। न मालूम कितने लोग भूखों मर जाएंगे क्योंकि उन्हें राशन की दुकानों से खाद्यान्न मिलेगा नहीं और शक्ति में हास होने के कारण बाजारों से वह आवश्यक सामग्री खरीद नहीं सकेंगे।

बिहार सरकार के साथ एवं आपूर्ति मंत्री ने भारत सरकार की खाद्यान्न कटौती की इस नीति का विरोध कर बिहार की करोड़ों जनता की आवाज को बुलन्द किया है।

मेरा भारत सरकार के कृषि मंत्री से अनुरोध होगा कि वह बिहार को मिलने वाले पचास हजार टन चावल और चौबीस हजार टन गेहूँ के कोटे में किसी भी प्रकार की कटौती नहीं करे। मेरा यह भी अनुरोध होगा कि वह बिहार की वर्तमान गम्भीर स्थिति को देखते हुए उसके कोटे में और वृद्धि करे ताकि कोई भूख से नहीं मरने पाए।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Prof. Madhu Dandavate. Professor, after you read it, the Minister has agreed to reply.